

भोपाल, यशभारत। बैंक से जुड़े जरूरी काम हैं तो उन्हें 23 से 25 सितंबर के बीच निपटाना सुविधाजनक रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (FBU) ने 28, 29 और 30 सितंबर 2026 को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का एलान किया है। इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण शाखाओं से जुड़ी सेवाओं पर लगातार पांच दिनों तक असर पड़ने की संभावना है।हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में नकद जमा और निकासी, चेक से जुड़े काम, दस्तावेज जमा करने तथा कर्मचारियों की सहायता से होने वाली अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए जिन ग्राहकों को शाखा जाकर जरूरी काम करना है, वे 23 से 25 सितंबर के बीच इसे पूरा कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है, हालांकि उनकी उपलब्धता संबंधित बैंक की व्यवस्था और तकनीकी स्थिति पर निर्भर करेगी।

भाजपा ने राज्यों में संगठन की कमान बदली

बैजयंत पांडा महाराष्ट्र के प्रभारी तावड़े को यूपी की जिम्मेदारी

मुंबई, यश भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। नई जिम्मेदारियों में कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभार सौंपा गया है। सबसे अहम बदलाव उत्तर प्रदेश में किया गया है, जहां विनोद तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ चार सह-प्रभारियों की टीम भी तैनात की गई है। यह नियुक्तियां ऐसे समय हुई हैं, जब भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्यों में संगठनात्मक तैयारियां तेज कर रही है।

नई सूची में स्मृति ईरानी, राम माधव, हरिश द्विवेदी, सतीश पूनिया और सुनील बंसल को दो-दो राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा, हरिश द्विवेदी को बिहार और कर्नाटक, सतीश पूनिया को जम्मू-कश्मीर और पंजाब, राम माधव को



तमिलनाडु और उत्तराखंड तथा सुनील बंसल को तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। अनिल एंटनी को नगालैंड का प्रभारी और गोवा का सह-प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र में भाजपा ने बैजयंत जय पांडा को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ अमित मालवीय और सदानंद शेट तानावड़े को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ जगदीश पटेल और मेधा कुलकर्णी सह प्रभारी के रूप में काम करेंगे। उत्तराखंड में राम माधव को प्रभारी तथा अरविंद मेनन और बासुरी



स्वराज को सह प्रभारी बनाया गया है। गुजरात में तरुण चुग प्रभारी होंगे, जबकि अजय महावर और गोमती साई सह प्रभारी बनाई गई हैं। राजस्थान की जिम्मेदारी संजय भाटिया को दी गई है। कविता पाटीदार और कुलजीत चहल सह प्रभारी होंगे। मध्य प्रदेश में बितलब कुमार देव प्रभारी और रेखा वर्मा सह प्रभारी होंगी। पार्टी ने ओडिशा, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी समेत अन्य राज्यों के लिए भी नए संगठनात्मक दायित्व तय किए हैं। उक्त जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है।

ड्यूटी में तंबाकू-शराब का सेवन पड़ेगा महंगा, पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

भाईंदर, यश भारत। मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान तंबाकू, गुटखा, मावा, खार सहित अन्य तंबाकू उत्पाद और शराब का सेवन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं विशेष शाखा) संजय कुमार पाटिल ने जारी आदेश में कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों



प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ऐसे व्यवहार से अनुशासन प्रभावित होता है। पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, सरकारी वाहन और ड्यूटी स्थल पर इन पदार्थों के सेवन पर रोक रहेगी। प्रभारी अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने तथा उल्लंघन मिलने पर नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव आयोग में दरार के दावे से सियासी तूफान मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष हमलावर

संघ-जोशी ने 10 माह में 14 बार दर्ज कार्रवाई आपत्ति, SIR और वोटर डेटा पर उठाए सवाल आयोग ने कहा- सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए

नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटींसिव रिविजन (स्ट्रक्चर) प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट ने बहस को और तेज कर दिया है। एक अंग्रेजी दैनिक की जांच के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों और जारी आदेशों पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों आयुक्तों ने कुछ फैसलों को अपनी जानकारी या सहमति के बिना लिए जाने का दावा किया और कुछ कदमों को 'अनिधिकृत' तथा 'अवैध' बताया। रिपोर्ट के मुताबिक, आपत्तियों का संबंध नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने, SIR से जुड़े मामलों में अपील तथा मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस और आईटी सिस्टम के नियंत्रण से था। चार आपत्तियां एक ही



दिन दर्ज किए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं।

फॉर्म-6 में बदलाव पर भी सवाल

रिपोर्ट के अनुसार, नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में SIR से जुड़े सवाल जोड़े जाने पर भी आपत्ति दर्ज की गई थी। इसमें नए मतदाता या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का पिछली SIR की मतदाता सूची में नाम होने से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। संधू और जोशी ने इस बदलाव की प्रक्रिया और अधिकार को लेकर सवाल उठाए थे। मतदाता डेटा के आईटी प्रबंधन को लेकर भी दोनों आयुक्तों ने

चिंता जताई। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने चुनावी रोल के डिजिटल सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक पहुंच को दिल्ली में केंद्रीकृत किए जाने पर सवाल उठाए तथा इस संबंध में कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखे। रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। कुछ विपक्षी नेताओं ने कुमार को हटाने की मांग भी उठाई है। इन मांगों को राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, चुनाव आयोग के सूत्रों ने रिपोर्ट में बताए गए आंतरिक मतभेद के दावे को खारिज किया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि SIR सहित सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी और सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग के इस पक्ष के मुताबिक, रिपोर्ट में उठाए गए मतभेदों को फैसलों पर अतिम असहमति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तीन सदस्यीय मौजूदा चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं। ऐसे में सामने आई लिखित आपत्तियों और आयोग के आधिकारिक स्पष्टीकरण के बीच अंतर ने SIR तथा चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चल रही बहस को और गंभीर बना दिया है।

नवा रायपुर में आग का गोला बनी सरकारी बस रायपुर,यशभारत।

नया रायपुर के महानदी गवन के समीप बुधवार शाम बड़ा हादसा टल गया, जब सड़कियालय के कर्मचारियों को ले जा रही एक चलती हुई बस में अचानक भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना के समय बस में 30 से अधिक शासकीय कर्मचारियों सवार थे, जो अपने दफ्तर का काम समाप्त कर वापस लौट रहे थे। अचानक लगी इस आग से मौके पर भारी अफस-तफरी मच गई और कर्मचारियों ने किसी तरह कूटकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस जब महानदी गवन के करीब से गुजर रही थी, तभी अचानक उसके इंजन और पिछले हिस्से से भारी मात्रा में धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटों ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। बस के भीतर मौजूद कर्मचारियों को जब तक स्थिति समझ आयी, तब तक धुएं के कारण अंदर घुसने जैसी स्थिति बन गई। झड़वर ने सुझबुझ दिखाते हुए बस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी। आग लगने के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। किसी अनजाने से बचने के लिए कर्मचारियों ने बिना एक पल गंगाए चलती और रुकती बस से नीचे कूटना शुरू कर दिया। गंभीरतम यह रही कि इस आपदाघापी में समय रहते सभी 30 से अधिक कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे।

मंत्रियों की 'वलास'-आज रिव्यू, तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली, यशभारत। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए बुधवार से दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया। 'विकसित भारत2047' की थीम पर आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ सरकार की प्राथमिकताओं, योजनाओं की प्रगति और जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। शिविर 24 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन मंत्रियों को अपने विभाग और क्षेत्र से जुड़े कामकाज पर प्रेजेंटेशन देना है। दूसरे दिन इन प्रस्तुतियों और काम की समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रियों के प्रदर्शन को 'एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और पुअर' जैसी श्रेणियों में आंका जा सकता है। तैयार रिपोर्ट कार्ड को भविष्य में कैबिनेट फेरबदल के दौरान भी आधार बनाए जाने की चर्चा है।



Gen z और रोजगार पर खास फोकस - चिंतन शिविर में युवाओं, खासकर तड़टु' के साथ संवाद, रोजगार

और मौजूदा मुद्दों को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। मंत्रियों से पूछा जाएगा कि उन्होंने युवाओं के साथ संवाद के लिए अब तक क्या कदम उठाए, उनके क्षेत्र में युवाओं के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या योजना बनाई गई है। UGC से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में बताए गए हैं। इसके अलावा महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधायी कदमों पर भी चर्चा और मंत्रियों से सुझाव लिए जाने की बात सामने आई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा था। इसी लक्ष्य के अनुरूप सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं और विकास की रणनीति पर शिविर में मंथन होगा।

दो दिन की यह बैठक मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के साथ-साथ युवा, रोजगार, महिला भागीदारी और विकसित भारत के रोडमैप पर सरकार की आगामी प्राथमिकताओं को आकार देने का मंच भी बनेगी।

मीराबाई ने रचा इतिहास, एशियाड में भारत को 28 साल बाद दिलाया भारोत्तोलन में पदक

49 किग्रा वर्ग में 198 किग्रा वजन उठाकर जीता रजत, एशियाई खेलों में पहली बार पदक से बढ़ाया देश का गौरव

आइची-नागोया, एजेंसी। भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए महिलाओं की 49 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। मीराबाई ने कुल 198 किग्रा वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। उनके इस पदक के साथ ही एशियाई खेलों में भारोत्तोलन में भारत का 28 साल से चला आ रहा पदक का इंतजार खत्म हो गया।

मीराबाई ने श्वैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 83 किग्रा से शुरुआत की। दूसरे प्रयास में उन्होंने 85 किग्रा और तीसरे प्रयास में 87 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया। श्वैच के बाद वह पदक की दौड़ में मजबूती से बनी हुई थीं। क्वीन एंड जर्क में भी मीराबाई ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रयास में 107 किग्रा और दूसरे प्रयास में 111 किग्रा वजन उठाया। इसके बाद उन्हें तीसरे प्रयास की आवश्यकता नहीं



पड़ी। इस तरह उनका कुल स्कोर 87 किग्रा श्वैच और 111 किग्रा क्वीन एंड जर्क मिलाकर 198 किग्रा रहा।

उत्तर कोरिया की रि सोंग गुम को स्वर्ण

स्पर्धा में उत्तर कोरिया की रि सोंग गुम ने 215 किग्रा के कुल वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने श्वैच में 94 किग्रा और क्वीन एंड जर्क में 121 किग्रा वजन उठाया। इंडोनेशिया की विजायाना लुलुक डियाना त्रि ने 191 किग्रा के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

1998 के बाद भारत को मिला पदक

मीराबाई के रजत पदक ने एशियाई खेलों में भारोत्तोलन के क्षेत्र में भारत का लंबा इंतजार समाप्त कर दिया। भारत ने इससे पहले 1998 बैकॉक एशियाई खेलों में

कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। उसके बाद भारतीय भारोत्तोलकों को एशियाई खेलों में पदक नहीं मिल सका था। मीराबाई ने 28 साल बाद इस सिलसिले को तोड़ दिया।

भारत की पदक तालिका में भी इजाफा

मीराबाई के रजत पदक से एशियाई खेलों में भारोत्तोलन में भारत के कुल पदकों की संख्या 15 हो गई है। इनमें छह रजत और नौ कांस्य पदक शामिल हैं। हालांकि, भारत अब तक एशियाई खेलों में भारोत्तोलन का स्वर्ण पदक नहीं जीत सका है। एशियाड के चौथे दिन भारत के पदकों की संख्या में अन्य स्पर्धाओं से भी इजाफा हुआ। शॉटगन शूटिंग के महिला स्कोट टीम इवेंट में रायजा दिब्लें, परिनारा धालीवाल और माहेश्वरी चौहान ने कांस्य पदक जीता।

पुरुष स्कोट टीम में अनंतजीत सिंह नारुका, मौराज अहमद खान और भवतेव सिंह गिल ने शूट-ऑफ में कजाकिस्तान को हराकर कांस्य हासिल किया। सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने भी भारत को पदक दिलाया। वहीं, निशानेबाजी की महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर 18.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। टीम स्पर्धा में भी भारतीय टीम मामूली अंतर से पदक से चूक गई।

अडानी फिर बने भारत के सबसे अमीर अंबानी से 59,400 करोड़ आगे



मुंबई, यश भारत। गौतम अडानी ने एक बार फिर भारत के सबसे अमीर कारोबारी का स्थान हासिल कर लिया है। एम3एम हरुन इंडिया चिच लिस्ट 2026 के मुताबिक अडानी परिवार की कुल संपत्ति बढ़कर 9.23 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसके साथ ही अडानी परिवार ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पीछे छोड़ दिया है।

अंबानी परिवार की कुल संपत्ति 8.63 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार अडानी परिवार की संपत्ति में पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, अंबानी परिवार की संपत्ति में करीब



10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। दोनों परिवारों की संपत्ति में अब लगभग 59,400 करोड़ रुपए का अंतर है। हरुन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। देश में अब 1,810 ऐसे लोग हैं, जिनकी कुल संपत्ति कम से कम 1,000 करोड़ रुपए है। वहीं, डॉलर अरबपतियों की संख्या बढ़कर 391 हो गई है। अडानी समूह का कारोबार बंदरगाह, ऊर्जा, हवाईअड्डे और बुनियादी ढांचे समेत कई क्षेत्रों में फैला है, जबकि रिलायंस समूह ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय है। अलग-अलग रिपोर्टों में संपत्ति की गणना की तारीख और पद्धति अलग होने से रैंकिंग में अंतर भी देखने को मिल सकता है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट जज एकमत नहीं

नई दिल्ली एजेंसी। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बंटा हुआ फैसला दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच को यह तय करना था कि केस बड़ी (पांच जजों की) बेंच को भेजा जाए या नहीं। 15 दिन तक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने केस 5 जजों की बड़ी संविधान बेंच को भेजने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं जस्टिस शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि दोनों जजों ने मामला CJI संयुक्तता के पास भेजने पर सहमति जताई है। अब CJI तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाई जाए या नहीं। बेंच ने बड़े संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए स्थायी 5 जजों की संविधान बेंच बनाने की संभावना तलाशने का भी अनुरोध किया है।

एआई से बदला युद्ध का चेहरा, ड्रोन बने नए हथियार

मदन गार्ग
जबलपुर। कभी शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में वीडियोग्राफी तथा फूल बरसाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन आज आधुनिक युद्ध के महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने ड्रोन की सैन्य उपयोगिता को व्यापक स्तर पर सामने रखा है। निगरानी से लेकर सटीक हमलों और काउंटर-ड्रोन अभियानों तक इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।



मंडराने के बाद लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम होते हैं। ड्रोन तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। इससे नेविगेशन, वस्तु पहचान और लक्ष्य की निगरानी जैसे कार्य अधिक स्वचालित हो सकते हैं। वहीं ड्रोन स्वयं में बड़ी संख्या में ड्रोन नेटवर्क के माध्यम से समन्वित तरीके से काम करते हैं। इससे एक साथ कई दिशाओं से कार्रवाई करने की क्षमता विकसित होती है।

रूस-यूक्रेन युद्ध को ड्रोन युद्ध के बड़े प्रयोगक्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। दोनों पक्षों ने निगरानी और हमलों के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। सितंबर 2026 में यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ एक बड़े अभियान में एक हजार से अधिक ड्रोन इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट सामने आई। इससे युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत ने भी ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक पर अपना ध्यान बढ़ाया है। भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ -9B ड्रोन की खरीद का अनुबंध किया है। इनमें 16 SeaGuardian और 15 SkyGuardian शामिल हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी की निगरानी और समुद्री क्षेत्र की निगरानी जैसे अभियानों में किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक का महत्व सामने आया। भारत की एकीकृत वायु-रक्षा और काउंटर-यूपएस प्रणालियों ने ड्रोन खतरों से निपटने

में भूमिका निभाई। इसके साथ ही स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियों के विकास पर जोर बढ़ा है। भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ड्रोन क्षमता बढ़ाने में जुटे हैं। पाकिस्तान ने चीन और तुर्किये के साथ सहयोग के जरिए अपनी मानवरहित हवाई क्षमता विकसित की है। बांग्लादेश ने चीन के साथ स्थानीय स्तर पर ड्रु निर्माण और असेंबली क्षमता विकसित करने के लिए समझौता किया है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ काउंटर-ड्रोन तकनीक भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। रेंडियो-फ्रीक्वेंसी जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, माइक्रोवेव और डायरेक्टेड-एनर्जी जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर, ड्रोन ने युद्ध की रणनीति और तकनीक दोनों को बदलना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में एआई, स्वयं संचालित प्रणालियां युद्धक्षेत्र की तस्वीर को और बदल सकती हैं। भारत के लिए चुनौती अत्याधुनिक ड्रोन बनाने के साथ-साथ मजबूत ड्रोन-रोधी सुरक्षा तंत्र विकसित करने की भी है।



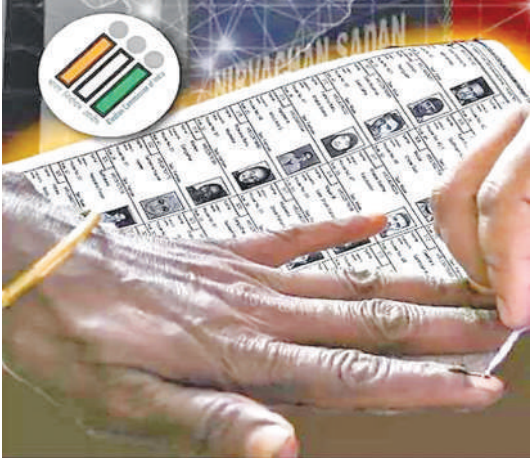
मुंबई में फिल्म और कॉन्सर्ट होंगे महंगे

मनोरंजन कर में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव

मुंबई, यश भारत। मुंबई में सिनेमा देखने और संगीत कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। बीएमसी ने मनोरंजन कर की दरों में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, कानून समिति ने प्रस्ताव को फिलहाल वापस भेजते हुए प्रशासन से दरों पर दोबारा विचार करने को कहा है।प्रस्ताव के मुताबिक वातानुकूलित सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में प्रति टिकट मनोरंजन कर 60 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तैयारी है। वहीं,

गैर-वातानुकूलित सिनेमाघरों में कर 45 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए किया जा सकता है। नाटक और संगीत कार्यक्रमों पर मनोरंजन कर 50 से बढ़ाकर 100 रुपए, जबकि अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों पर 30 से बढ़ाकर 75 रुपए करने का प्रस्ताव है।मिनी थिएटर और वीडियो प्रदर्शन के लिए पहली बार 90 रुपए कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बीएमसी का कहना है कि मनोरंजन कर की मौजूदा दरों में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है। प्रस्ताव लागू होने पर बीएमसी की वार्षिक आय करीब 360 करोड़ रुपए से बढ़कर 500-550 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

मुंबई में 26 और 27 सितंबर को विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर



मुंबई, यश भारत। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2026 के तहत मुंबई के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 26 और 27 सितंबर को विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। बृह-मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की ओर से आयोजित इन शिविरों में नागरिकों

तथा नाम, पता और अन्य विवरणों में सुधार या अद्यतन के लिए आवश्यक पत्र उपलब्ध रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने नागरिकों से 26 और 27 सितंबर के विशेष शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है।

आपात चिकित्सा सेवा को मिलेगी मजबूती, 150 एंबुलेंस जल्द सड़कों पर

मुंबई, यश भारत। महाराष्ट्र सरकार की आपातकालीन चिकित्सा सेवा परियोजना के तहत नई 108 एंबुलेंस जल्द ही सरकारी सेवा में शामिल की जाएंगी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन एंबुलेंस का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और इन्हें जल्द से जल्द सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा के तहत कुल 1,756 एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें 255 उन्नत जीवनरक्षक (एएलएस) और 1,204 मूलभूत जीवनरक्षक एंबुलेंस शामिल हैं। इसके अलावा 36 नवजात शिशुओं के लिए विशेष एंबुलेंस, 166 दोपहिया एंबुलेंस, 15 नदी एंबुलेंस और 10 समुद्री एंबुलेंस भी सेवा का हिस्सा होंगी।पूरी तरह भारतीय निर्माण वाली इन एंबुलेंस में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी), परिवहन श्वासयंत्र, नाड़ी ऑक्सीमीटर, सक्शन पंप और ऑक्सीजन वितरण प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल के चिकित्सकों से सीधे संपर्क की सुविधा भी इसमें दी गई है, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के



जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए गए 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत पहले चरण में 150 एंबुलेंस नागरिकों की सेवा में शामिल करने का सरकार का प्रयास है।

बाप्पा के दरबार में रक्तदान का महाअभियान

भिंवंडी, यश भारत। धामनकर नाका मित्र मंडल और स्वाभिमान सेवा संस्था की ओर से गणेशोत्सव के अवसर पर आयोजित महा-रक्तदान शिविर में 417 लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को हेलमेट भेंट किए गए। 'एकात्मतेचा राजा' के नाम से प्रसिद्ध मंडल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के जन्मदिन के अवसर पर शिविर आयोजित किया। शहराध्यक्ष रवि सावंत ने उद्घाटन किया, जबकि विधायक निरंजन डाखरे ने रक्तदाताओं को हेलमेट वितरित किए।मंडल ने श्री भैरव चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के सहयोग से मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया। इसमें 300 मरीजों



की जांच हुई और 221 जरूरतमंदों को मुफ्त चश्मे दिए गए। जांच में 25 मरीजों में मोतिवाबिंद पाया गया, जिनकी सर्जरी मंडल की ओर से मुफ्त कराई जाएगी।मंडल अध्यक्ष संतोष शेड्ढी ने बताया कि संस्था पिछले सात वर्षों से रक्तदान और पांच वर्षों से नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर रही है।

फ्रिज में मांस का खून, कॉकरोच और चींटियां मिलीं

रेस्तरां का लाइसेंस निलंबित

मुंबई, यश भारत। मुंबई के मशहूर महलक्ष्मी रेसकोर्स स्थित गैलॉप्स रेस्तरां पर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है। त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के दौरान अधिकारियों को रेस्तरां की रसोई और भंडारण व्यवस्था में कई गंभीर खामियां मिलीं।

जानकारी के अनुसार, रेफ्रिजरेटर में मांसाहारी खाद्य पदार्थों से निकला खून और केचप के दाग बर्फ पर मिले। इसके अलावा रसोई में जीवित कॉकरोच और चींटियां भी पाई गईं। जांच में कच्चे खाद्य पदार्थों की



पैकिंग फटी और क्षतिग्रस्त मिली। दीवारों की हालत खराब थी, नालियों की पर्याप्त ढकाई नहीं थी और कई जगह पानी जमा पाया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि खाद्य कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सकीय जांच और टीकाकरण से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड

मरम्मत में भी पेशानी होती है।एसोसिएशन के अनुसार, कुछ वर्ष पहले टूटे केबल के खिड़की से टकराने की घटना भी सामने आ चुकी है। नागरिकों ने दक्षिण मुंबई के अन्य इलाकों की तरह मरीन ड्राइव में भी भूमिगत केबल डकट बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि बेतरतीब केबल मरीन ड्राइव की खूबसूरती और ऐतिहासिक पहचान को प्रभावित कर रहे हैं। मरीन ड्राइव आर्ट डेको हेरिटेज क्षेत्र का खतरा बना रहता है। इससे पश्चिम के तारों में फंसने और इमारतों की

रंगदारी के लिए प्राइवेट जासूसों का सहारा लेता था रवि पुजारी

पूर्व आईएएस से 10 करोड़ मांगने के मामले में आरोप तय

जय सिंह, यश भारत। कुख्यात गैंगस्टर रवि पुजारी के खिलाफ रंगदारी के मामलों में प्राइवेट जासूसों के कथित इस्तेमाल का पहलू सामने आया है। वर्ष 2017 में पूर्व आईएएस अधिकारी राधेश्याम मोपलवार से 10 करोड़ रुपए की कथित रंगदारी मांगने के मामले में विशेष मकोका अदालत ने आरोप तय किए हैं।

पुलिस के अनुसार, मोपलवार को कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग



सार्वजनिक करने की धमकी देकर पहले 10 करोड़ रुपए मागे गए, बाद में रकम घटाकर 7 करोड़ रुपए करने का आरोप है।

जांच में प्राइवेट जासूस सतीश मंगले का नाम सामने आया, जिसे कथित तौर पर एक करोड़ रुपए लेते गिरफ्तार किया गया

था। अभियोजन का दावा है कि रंगदारी के लिए जासूसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। मामले में विदेश से धमकी भरे फोन आने और फोन करने वाले के स्वयं को रवि पुजारी बताने का भी आरोप है। हालांकि, 2023 में अदालत ने सतीश मंगले, उनकी पत्नी श्रद्धा और अतुल तांबे को बरी कर दिया था तथा जांच में कमियां बताई थीं। दूसरे मामले में पुजारी पर आतंक अहमद खलील अहमद शेख से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार, पांच लाख रुपए की किस्त भी ली गई थी। दोनों मामलों में अब सुनवाई आगे बढ़ेगी।

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता पर सवाल



न्यायमूर्ति आर.सी. चव्हाण ने समिति से दिया इस्तीफा

मुंबई, यश भारत। महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया के बीच सेवानिवृत्त बांबे

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर.सी. चव्हाण ने समिति से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 19 सितंबर को इस्तीफा दिया था। चव्हाण ने सार्वजनिक सुझाव लेने की प्रक्रिया और समिति की बैठक में एक गैर-सदस्य की मौजूदगी को लेकर आपत्ति जताई। राज्य सरकार ने जुलाई

में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति को महाराष्ट्र में यूसीसी के प्रारूप और उसके क्रियान्वयन से संबंधित सिफारिशें तैयार करनी हैं। चव्हाण के अनुसार, जनता से राय लेने के लिए तैयार प्रश्नावली में केवल 'हां' या 'नहीं' के जवाब तक सीमित रहने के बजाय लोगों को विस्तृत राय देने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने तथा कम से कम 10 हजार प्रतिक्रियाएं जुटाने का सुझाव दिया था। चव्हाण ने कहा कि व्यक्तिगत जीवन में सरकार और कानून का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए।

मरीन ड्राइव में केबलों का जाल

भूमिगत डकट की मांग

मुंबई, यश भारत। दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक मरीन ड्राइव इलाके में इमारतों के बीच लटकते और उलझे केबलों को लेकर स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है। मरीन ड्राइव सिटीजन एसोसिएशन ने बीएमसी से केबलों को भूमिगत डकट में डालने और अनुपयोगी तारों को हटाने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि कई केबल छतों और इमारतों के बीच खींचे गए हैं, जिससे तार टूटने या गिरने की स्थिति में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इससे पश्चिम के तारों में फंसने और इमारतों की

मरम्मत में भी पेशानी होती है।एसोसिएशन के अनुसार, कुछ वर्ष पहले टूटे केबल के खिड़की से टकराने की घटना भी सामने आ चुकी है। नागरिकों ने दक्षिण मुंबई के अन्य इलाकों की तरह मरीन ड्राइव में भी भूमिगत केबल डकट बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि बेतरतीब केबल मरीन ड्राइव की खूबसूरती और ऐतिहासिक पहचान को प्रभावित कर रहे हैं। मरीन ड्राइव आर्ट डेको हेरिटेज क्षेत्र का खतरा बना रहता है। इससे पश्चिम के तारों में फंसने और इमारतों की



फनल जोन की इमारतों के पुनर्विकास का रास्ता होगा आसान

मुंबई, यश भारत। मुंबई एयरपोर्ट के फनल जोन में ऊंचाई प्रतिबंधों के कारण वर्षों से अटकी पुनर्विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार एफएसआई क्लबिंग के प्रस्ताव पर विचार पर विचार कर रही है। इसके तहत किसी भूखंड पर विमान सुरक्षा नियमों के कारण इस्तेमाल नहीं हो पाने वाली एफएसआई को दूसरे पुनर्विकास प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने की अनुमति देने का विकल्प तलाश जा रहा है।फनल जोन में विले पार्ले, सांताक्रूज, कुर्ला समेत कई इलाकों की पुरानी इमारतें शामिल हैं। विमान परिचालन की सुरक्षा के लिए यहां भवनों की ऊंचाई सीमित है। परिणामस्वरूप कई भूखंडों पर अनुमत एफएसआई का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इससे पुनर्विकास परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित होती है और पुरानी इमारतों में रहने वाले लोगों को भी वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है।विधायक पराग अलवणी और अमित साटम ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में बीएमसी से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर एफएसआई क्लबिंग की व्यवहार्यता और नियमों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।



इमिटेशन ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर 11 लाख रुपए चोरी

मुंबई, यश भारत। जुम्मा मस्जिद के पास न्यू कटलरी मार्केट में इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर करीब 11 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गया। रविवार को दुकान बंद होने का फायदा उठाकर हुई इस वारदात से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। एल.टी. मार्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, मुंबई सेंट्रल निवासी मेहबूब यूसुफ खान की इस्माइल बिल्डिंग में इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान है। व्यापारियों को ज्वेलरी खरीद के भुगतान के लिए उन्होंने दुकान के ड्रॉवर में करीब 11 लाख रुपए रखे थे। शनिवार रात करीब आठ बजे दुकान बंद कर वे घर चले गए।रविवार रात करीब सवा दस बजे मार्केट के सुरक्षा रक्षक तनवीर ने उनके भाई को फोन कर ताला टूटे होने की जानकारी दी। दुकान पहुंचने पर सामान व्यवस्थित मिला, लेकिन ड्रॉवर से नकदी गायब थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया है। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश की जा रही है।



फेरीवालों के लिए लोककल्याण मेला संपन्न

मुंबई, यश भारत। बृह-मुंबई महानगरपालिका के के/दक्षिण विभाग, नियोजन विभाग और अनुज्ञापन विभाग की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोककल्याण मेले का आयोजन किया गया। मेले में फेरीवालों, महिला बचत समूहों तथा इच्छुक महिला-पुरुषों को योजना की जानकारी दी गई। पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध रूप से 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।मेले में डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण तथा एफ एस एस ए आई के सहयोग से स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी दिनेश निषंवने, के/पूर्व अनुज्ञापन अधिकारी उत्तम सरवदे, बैंक अधिकारी महेश गुप्ता, संजय दहिया तथा मुंबई नगर पथ विक्रेता समिति के सदस्य जयशंकर सिंह, लव कुश तिवारी, रमेश गुप्ता, अनिल सहित सैकड़ों फेरीवाले उपस्थित रहे।

अस्पताल में अग्रवाल समाज ने शुरू किया शीतल जल प्याऊ

उल्हासनगर, यश भारत। गर्मी के मौसम में मरीजों और उनके परिजनों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अग्रवाल समाज, कल्याण की ओर से उल्हासनगर के मध्यवर्ती अस्पताल में 32वें शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ किया गया। समाज की ओर से लगाए गए सभी 32 प्याऊ नियमित रूप से संचालित होने की जानकारी दी गई।

समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गर्ग ने बताया कि अस्पताल परिसर में स्थापित यह प्याऊ श्रीमती एवं श्री पुरुषोत्तम लाल मदन लाल भीमराजका के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन समाजसेवी एवं उद्योगपति महेंद्र मांगीलाल अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रकाश खेतान ने भी समाज के सामाजिक सेवा कार्यों की प्रशंसा की और ऐसे जनोपयोगी कार्यों में सहयोग करने की इच्छा जताई। कार्यक्रम का संचालन समाज के वी.पी. भित्तल ने किया। इस अवसर पर निमित्त अग्रवाल, राजीव गुप्ता, महेश शाह, अनिल बंसल, तुलसीराम बंसल, अनूप बंसल, आत्माराम डिडवानिया, नरेश पी. भीमराजका सहित समाज के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

सिंहस्थ की आहट, शिर्डी में तैयारियां तेज

पांच वाहनतलों और अतिरिक्त अन्नछत्र से संभलेगी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़

नासिक, यश भारत। नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के शिर्डी पहुंचने की संभावना को देखते हुए शहर में भीड़ और यातायात प्रबंधन बड़ी चुनौती बन सकता है। इसे देखते हुए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए शिर्डी के आसपास पांच बड़े वाहनतल विकसित करने की योजना है। यहां शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोका जाएगा, जिससे मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने और जाम से राहत मिलने की उम्मीद



है। श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त अन्नछत्र शुरू करने की भी तैयारी है। साई संस्थान की ओर से भोजन और महाप्रसाद की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को समय पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा

सड़क चौड़ीकरण, पेयजल, स्वच्छता, पाकिंग और अस्थायी आवास जैसी सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिंहस्थ शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होगी।



चुनाव आयोग के भीतर मतभेद पर उद्भव ठाकरे का हमला

ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग, फैसलों की प्रक्रिया पर उठे सवाल

मुंबई, यशभारत। चुनाव आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों को लेकर कथित मतभेद सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

जानकारी के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में कई मौकों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की निर्णय प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, दोबारा नाम दर्ज करने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसले शामिल बताए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर शिवसेना (उद्भव बालासाहेब ठाकरे) के



प्रमुख उद्भव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। ठाकरे गुट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है। उनका

कहना है कि यदि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के भीतर ही महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं, तो उसकी कार्यप्रणाली को लेकर

स्पष्टीकरण जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ मामलों में चुनाव आयुक्तों ने संबंधित निर्णयों से पहले पर्याप्त जानकारी साझा नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई। मतदाता सूची से जुड़े तकनीकी काम के केंद्रीकरण और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। एक लिखित आपत्ति में आयोग के एक निर्णय की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर अलग-अलग सभी बिंदुओं को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आयोग का कहना है कि एसआईआर से संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

‘जब संस्था के भीतर ही आरोप हैं तो भरोसा किस पर करें?’

निर्वाचन आयोग में मतभेद पर सुप्रिया सुले का सवाल

मुंबई, यशभारत। केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयोग के दो अन्य सदस्यों के बीच मतभेद सामने आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के भीतर से ही आरोप सामने आना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।



कर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जुड़े सवाल पर सुले ने कहा कि इस मामले में नैतिकता का परिचय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है। सुले ने कहा कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक नागरिक को समान मताधिकार सविधान ने दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक भी हो सकती है। वहीं, महाराष्ट्र में सुखे जैसी स्थिति को लेकर सुले ने सरकार से किसानों के पक्ष में ठोस सहायता देने की मांग की।

सूखे जैसे हालात पर फडणवीस का अलर्ट

मंत्रियों को सर्वे के आदेश, किसानों को राहत की तैयारी



नागपुर, यशभारत। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश के लंबे अंतराल से पैदा हुए सूखे जैसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में प्राथमिक अकलन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में संभावित नुकसान का जायजा लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू करने के संकेत दिए हैं।

फडणवीस ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में बारिश की स्थिति और फसलों पर पड़े असर की समीक्षा की गई। कई क्षेत्रों में बारिश के

लंबे अंतराल के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक सप्ताह में प्राथमिक समीक्षा पूरी की जाएगी। इसके बाद आधिकारिक फसल सर्वेक्षण कराया जाएगा और प्रभावित किसानों को सहायता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया भी जारी है। अब तक तीन सूचियां जारी की जा चुकी हैं और शेष सूचियों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में पीने के पानी और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर भी सरकार का ध्यान है। संभावित अल नीनो प्रभाव को देखते हुए पहले से तैयारी की जा रही थी। चारे की कमी दूर करने के लिए 'वैरन विकास' कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसानों को शाम के समय अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। इससे पहले शवद पवार ने 18 सितंबर को राज्य में सूखा घोषित कर प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज देने की मांग की थी।

कैंग रिपोर्ट के बाद मध्य रेल का बड़ा जल गुणवत्ता अभियान

2,967 स्थानों की जांच
1,753 टंकियां साफ, 349 नमूनों में नहीं मिला ई. कोलाई

मुंबई, यशभारत। गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैंग) की रिपोर्ट के बाद मध्य रेल के मुंबई मंडल ने जल गुणवत्ता को लेकर विशेष अभियान चलाया। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर स्टेशनों, रेलवे कॉलोनिजों और कार्यस्थलों पर पानी के स्रोतों और वितरण व्यवस्था की व्यापक जांच की गई।

अभियान के दौरान जल स्रोत, फिल्ट्रेशन संयंत्र, भूमिगत और ऊपरी पानी की टंकियों, जल बूथ, नलों तथा वितरण केंद्रों समेत 2,967 स्थानों की जांच की गई। इनमें 410 कमियां सामने आईं, जिनमें 365 को दूर कर दिया गया है, जबकि 45 पर काम जारी है। 20 अगस्त से 22 सितंबर के बीच मंडल



की 2,913 पानी की टंकियों में से 1,753 की सफाई की गई। इसके अलावा 1,716 स्थानों पर वेंट और ओवरफ्लो पाइप पर मजबूत ढक्कन व जालियां लगाई गईं। जल गुणवत्ता की जांच के लिए 349 नमूने लिए गए। भौतिक, रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण में किसी भी नमूने में ई. कोलाई या अन्य बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण नहीं मिला। 134 स्थानों पर रोजाना अवशिट क्लोरीन की निगरानी की जा रही है। सीएसएमटी, कल्याण, भिवंडी रोड और लोनावला में जल पाइपलाइन व्यवस्था की भी जांच की गई। रेलवे के अनुसार, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी का काम आगे भी जारी रहेगा।

मुंबईकरों को मिलावटी धी परोस रहा था 'गुरुकृपा' का मालिक

सूरजमुखी तेल और वनस्पति धी मिलाकर तैयार किया जा रहा था 'पूजा धी', 15.15 लाख रुपये का माल जप्त

मुंबई, यशभारत। त्योहारी मौसम में धी और मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मालाड पूर्व स्थित मेसर्स गुरुकृपा डेयरी उत्पाद में रिफाईंड सूरजमुखी तेल और वनस्पति धी मिलाकर कथित तौर पर 'पूजा धी' तैयार किए जाने का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान एफडीए ने डेयरी का खाद्य लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया।



भी मिले। अंधेरी के मेसर्स गुफरान सीख कॉर्नर में बिना वैध खाद्य लाइसेंस कारोबार चलता मिला। यहां स्वच्छता, भंडारण, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया। एफडीए ने कारोबार बंद करने के आदेश

दिए हैं। वहीं, महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित मेसर्स बीजेआरएस (गैलौफ़) रेस्तरां की रसोई में गंदगी, खून और केचप के दाग, तिलचट्टे, चींटियां और जलभराव जैसी गंभीर खामियां मिलीं। प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है।

लातूर में 1972 से भी गंभीर सूखा

फसलें बर्बाद, पानी-चारे का संकट फडणवीस ने दिया मदद का भरोसा

लातूर, यशभारत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को लातूर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। खेतों में फसलों को हुए नुकसान के साथ पानी और चारे की कमी को देखते हुए उन्होंने हालात को बेहद गंभीर बताया। फडणवीस ने कहा कि कुछ इलाकों में इस बार की स्थिति 1972 के भीषण सूखे से भी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को व्यापक स्तर पर सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि किसानों को नियमों का हवाला देकर राहत से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, नुकसान का पंचनामा करना कानूनी प्रक्रिया है और इसे पूरा करना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की कोशिश केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वास्तविक नुकसान के आधार पर सहायता पहुंचाई जाएगी। फडणवीस ने प्रशासन को सूखे की स्थिति का विस्तृत आकलन कर आवश्यक उपचारों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मराठवाड़ा के कई हिस्सों में पानी और पशुओं के चारे का संकट गहराने के बीच सरकार ने प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और स्थिति के अनुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय सम्मान मिलते ही बाप्पा की शरण में कार्तिक



लालबाग के राजा के चरणों में अर्पित किया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

मुंबई, यशभारत। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद सबसे पहले लालबाग पहुंच कर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया। 'चंद्र चैपियन' में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के बाद कार्तिक अपने सम्मान को साथ लेकर मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने पुरस्कार बाप्पा के चरणों में अर्पित किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कार्तिक नीले कुर्ते और सफेद पायजामे में लालबाग के राजा के सामने नतमस्तक दिखाई

दे रहे हैं। पुरस्कार बाप्पा को समर्पित करने के बाद उन्होंने गणपति का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। राष्ट्रीय सम्मान के तुरंत बाद मंदिर पहुंचने के उनके इस अंदाज की प्रशंसाकों ने सराहना की। कार्तिक को यह पुरस्कार 2024 में रिलीज हुई 'चंद्र चैपियन' में पौरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की भूमिका के लिए मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। पुरस्कार मिलने के बाद कार्तिक ने अपने ग्वालियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि छोटे शहर से अभिनेता बनने का सपना देखना आसान नहीं था। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय निर्देशक कबीर खान और निर्माता साजिद नाडियाडवाला को भी दिया।

बीएमसी पहली बार बॉन्ड से जुटाएगी 9,500 करोड़

मुंबई के बड़े प्रकल्पों को मिलेगा फंड, मार्च 2027 तक पहली बिक्री की तैयारी



मुंबई, यशभारत। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) वर्ष 2027 की शुरुआत में पहली बार नगर निकाय बॉन्ड जारी कर करीब 9,500 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी से कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, बॉन्ड की पहली बिक्री मार्च 2027 तक होने की संभावना है। यह राशि एक या अधिक चरणों में जुटाई जा सकती है।

बॉन्ड के जरिए जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल मुंबई की बुनियादी सुविधाओं और बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। इनमें परिवहन, जलापूर्ति, सीवेज और अन्य शहरी आधारभूत ढांचा परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। इससे बीएमसी को पारंपरिक बैंक ऋण के अलावा पूंजी बाजार से सीधे

धन जुटाने का विकल्प मिलेगा। प्रस्तावित 9,500 करोड़ रुपये की बॉन्ड बिक्री को किसी संवैधानिक स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित सबसे बड़े बॉन्ड निर्गमों में से एक माना जा रहा है। महाराष्ट्र के कई अन्य नगर निकाय भी विकास कार्यों के लिए बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नगर निकायों को अपने बड़े प्रकल्पों के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बॉन्ड बाजार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीएमसी की प्रस्तावित पहल से मुंबई की विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की उम्मीद है। हालांकि, बॉन्ड जारी करने की अंतिम समयसीमा और शर्तों को लेकर आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।

सड़क हादसे पर लगेगा तकनीक का ब्रेक

हर 50 किमी पर ट्रेंमा सेंटर 'गोल्डन ऑवर' में मिलेगा तत्काल उपचार



मुंबई, यशभारत। राज्य में सड़क हादसों और दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए परिवहन, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण और स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। दुर्घटना रोकने के लिए आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल, सड़क सुरक्षा ऑडिट और हादसे के बाद घायलों को 'गोल्डन ऑवर' में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाए। यह निर्देश परिवहन मंत्री तथा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने दिए। मंत्रालय में आयोजित 13वीं राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सरनाईक ने कहा कि 'पीएम-राहत' योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अधिकतम सात दिनों तक डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेस उपचार उपलब्ध है। उपचार शुरू करने में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य, पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त कार्यप्रणाली तैयार करें। उन्होंने 108 और निजी एंबुलेंस को एक डिजिटल मंच से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। एंबुलेंस में कैमरा और दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाएगा, ताकि अस्पताल के चिकित्सक रास्ते में ही

मरीज की स्थिति देखकर आवश्यक उपचार संबंधी मार्गदर्शन दे सकें। राज्य में प्रत्येक 50 किलोमीटर के दायरे में सक्षम ट्रेंमा सेंटर विकसित करने की योजना बनाने तथा समृद्धि महामार्ग, द्रुतगति मार्ग, समुद्री मार्ग और दुर्गम क्षेत्रों के लिए हवाई एंबुलेंस नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। सरनाईक ने सड़क निर्माण और रखरखाव के हर चरण में सुरक्षा ऑडिट करने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का 10 प्रतिशत हिस्सा सड़क सुरक्षा के लिए रखने को कहा। हादसों के 'ब्लैक स्पॉट' का वैज्ञानिक विश्लेषण कर वहां सुधार कार्य तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि जनवरी से जुलाई 2026 के बीच पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 6 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2025 में दुर्घटना मृतकों में 60 प्रतिशत दोपहिया वाहन चालक और 22 प्रतिशत पैदल यात्री थे। इसलिए इन दोनों वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

बांस से बनेगा इथेनॉल!

27 सितंबर को मुंबई में 'बांस अर्थव्यवस्था' पर मंथन, 50 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य

मुंबई, यशभारत। महाराष्ट्र में बांस को उद्योग, ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। इसी दिशा में मुंबई में 27 सितंबर को 'बांस अर्थव्यवस्था



एवं सतत विकास सम्मेलन-2026' आयोजित किया जाएगा। वेस्टर्न मुंबई पवई लेक में होने वाले इस सम्मेलन में बांस से इथेनॉल उत्पादन, जैव ऊर्जा, निर्माण क्षेत्र, कार्बन क्रेडिट, किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

महाराष्ट्र सरकार की बांस उद्योग नीति-2025 के तहत राज्य में करीब 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश, पांच लाख से

निवेशकों, उद्योग जगत, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं की भागीदारी होगी। बांस को निर्माण सामग्री के साथ-साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। बांस से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल बनाने की तकनीक देश में पहले से इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में बांस आधारित जैव ईंधन उद्योग की संभावनाओं पर भी मंथन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संपादकीय



आईआईटी की चमक के पीछे घुटता छात्र जीवन 45 मौतें और एक बड़ा सवाल

आईआईटी में आत्महत्या के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे देश की सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा एक असहज सवाल हैं। पांच साल में 23 आईआईटी में 45 छात्रों ने आत्महत्या की। यानी औसतन लगभग हर डेढ़ महीने में एक छात्र। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे अलग-अलग परिसरों की व्यक्तिगत घटनाओं में बाँटकर देखने से असली तस्वीर धुंधली पड़ जाती है। और आंकड़ों का दूसरा पहलू और भी गंभीर है। इन 45 छात्रों में 28 एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से थे—यानी कुल मामलों के 62 प्रतिशत से अधिक। इनमें 12 ओबीसी, नौ एससी और सात एसटी छात्र थे। दूसरी ओर 16 सामान्य वर्ग और एक इंडब्ल्यूएस छात्र था। यह आंकड़ा अपने आप में किसी कारण का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह जरूर बताता है कि सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के सवालों को नजरअंदाज करके समस्या को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता।

साल-दर-साल तस्वीर भी बेचैन करने वाली है। 2022-23 में जहां छह आत्महत्याएं दर्ज हुईं, वहीं 2023-24 में यह संख्या छलांग लगाकर 16 पहुंच गई—यानी एक साल में करीब 167 प्रतिशत की वृद्धि। 2024-25 में भी 13 मौतें हुईं। पांच वर्षों में अकेले आईआईटी हैदराबाद में सात, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली और कानपुर में छह-छह, मद्रास में पांच और आईआईटी (बीएचएच) वाराणसी में चार आत्महत्याएं दर्ज हुईं।

इन 45 मौतों के अलावा इसी अवधि में आठ अप्राकृतिक मौतें भी दर्ज हुईं, जिन्हें आत्महत्या के आंकड़े में शामिल नहीं किया गया। यानी परिसर में छात्रों की असामयिक मौतों का दायरा केवल 45 तक सीमित नहीं है।

ऐसे में आईआईटी मुंबई की हालिया घटना को भी केवल एक अलग घटना मानकर भूल जाना आसान रास्ता होगा। परीक्षा में कथित अनियमितता से शुरू हुआ मामला एक युवा जीवन के अंत तक पहुंच गया। यहां अनुशासन और परीक्षा की शुचिता अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या संस्थानों के पास संकट में फंसे विद्यार्थी को संभालने की पर्याप्त व्यवस्था है?

45 आत्महत्याएं किसी एक छात्र की कहानी नहीं, व्यवस्था के सामने रखी गई 45 चेतावनियाँ हैं। अगर हर मौत के बाद संवेदना व्यक्त करके मामला बंद हो जाता है, तो आंकड़े बढ़ते रहेंगे और कारण हमारी नजरों से छिपे रहेंगे। अब जरूरत आंकड़े गिनने की नहीं, हर आंकड़े के पीछे छिपे सवाल का जवाब खोजने की है।

कड़वे वचन

आदमी जब अपनीलड़कीके लिए लड़का देखने जाता है तो पत्नी पति से कहती किदो बातों का ध्यान रखना एक लड़का खाते पीते घर का हो। दो मगर खता पीता नहीं हो। दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है पर समझने वाला इसका मतलब समझता है। फिर पता नहीं क्यों लोग जिंदगी का मतलब नहीं समझते। अरे भाइ जीना है तो जीना (सीढ़ियां) तो चढ़ना ही पड़ेगा।

आज का राशिफल

पंचांग:- 24 सितंबर 2026

दिन-शुक्रवार, माह-भाद्र शुक्ल पक्ष

विक्रम संवत् 2083

मेघ

सू.रे.ची.रा.ली.शु.ले.ली.आ

दिन खुशनुमा रहने वाला है किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है

तूष

इ.स.ए.आ.ची.रा.शु.रे.ची

पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है धैर्य के साथ आगे बढ़े

मिथुन

का.मी.कु.म.रा.शु.के.मी.ठ

आज का दिन व्यापार के लिए कोई नई योजना बनावे के लिए है सफलता मिलेगी

कर्क

ली.इ.ह.रे.मी.शु.ली.इ.रे.मी

आज का दिन रचनात्मक कार्य करने में व्यतीत होने वाला है अपनी सुख सुविधाओं के सामान पर खर्च कर सकते हैं

सिंह

मा.मी.शु.मी.मी.रा.रे.इ.रे

दिन बुद्धि व विवेक से निर्णय लेने के लिए रहने वाला है आत्मविश्वास में वृद्धि होगी

कन्या

दी.षा.मी.रे.मी.रा.इ.रे.मी

विद्यार्थी वर्ग को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करें

तुला

रा.री.रु.रे.रे.रा.ली.शु.रे.मी

निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ ले बड़ों की सलाह को मानकर कार्य करें

धनु

मे.मी.मा.मी.शु.रा.का.दा.मे

दिल लाभदायक रहने वाला है मान सम्मान में वृद्धि होगी

कुंभ

शु.रे.मी.शु.रे.मी.शु.रे.मी.दा

दिन भर आलस महसूस कर करेगे कार्य पूरे होने में रुकावट आ सकती है

ज्योतिषाचार्य वीरेंद्र लोकेश व्यास

विचार प्रवाह

हरित खेती का हिसाब खेत से मंडी तक: किसान की जेब में कितना बचा

मौसम अब सिर्फ मौसम नहीं रहा। किसान के लिए यह उसकी फसल का हिसाब है। बारिश कब होगी, कितनी होगी, गर्मी कितनी पड़ेगी और फसल पकने के समय मौसम साथ देगा या नहीं—इन सवालों के जवाब पहले जैसे तय नहीं रहे। किसान जलवायु परिवर्तन को किसी रिपोर्ट या सम्मेलन की भाषा में नहीं समझता। वह इसे खेत में महसूस करता है। कभी फसल के नुकसान में, कभी बढ़ती सिंचाई लागत में और कभी एक ही मौसम में बदलते फैसलों में। 19 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी ह्रत्नन्न के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स’ का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारत के प्रयासों की तस्वीर सामने रखी। खेती और गांव भी इस तस्वीर का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत करीब साढ़े 12 लाख हेक्टेयर में 24 हजार प्राकृतिक खेती क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। उन्होंने करीब तीन हजार जलवायु-अनुकूल फसल किस्में विकसित होने की भी बात कही। जल संरक्षण के संदर्भ में 70 हजार से अधिक अमृत सरोवर और ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत करीब डेढ़ करोड़ वर्षाजल संचयन संरचनाओं का जिक्र भी उनके भाषण में आया। तस्वीर बड़ी है। आंकड़े भी बड़े हैं। लेकिन खेत में खड़े किसान के लिए सवाल थोड़ा अलग है। इन बदलावों से उसकी खेती कितनी बदली? प्राकृतिक खेती का क्षेत्र बढ़ना एक उपलब्धि हो सकती है। जल संरक्षण के लिए ढांचा खड़ा होना भी जरूरी है। जलवायु के अनुकूल बीज विकसित होना भी समय की जरूरत है। लेकिन किसान के लिए इन सबका मतलब आखिर क्या है?

खेती की लागत कितनी कम हुई?

फसल कितनी सुरक्षित हुई? और सबसे आखिर में—उसके हाथ में कितना बचा? यहीं से पर्यावरण की चर्चा किसान की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। किसान को बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली और मजदूरी का खर्च उठाना पड़ता है। ऊपर से मौसम का जोखिम। ऐसे में प्राकृतिक खेती से अगर बाहरी इनपुट पर निर्भरा घटती है और मिट्टी की सेहत सुधरती है तो यह किसान के लिए राहत हो सकती है। सरकार भी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को लागत कम करने, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने और टिकाऊ कृषि को

बढ़ावा देने से जोड़ती है। इस मिशन के तहत किसानों को दो वर्षों तक प्रति एकड़ सालाना चार हजार रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाता है, अधिकतम एक एकड़ तक। लेकिन किसान के सामने एक और सवाल है कि बदलाव का जोखिम कौन उठाएगा? अगर वह खेती का तरीका बदलता है और शुरूआती दौर में उपज प्रभावित होती है तो क्या होगा? नई पद्धति की जानकारी नहीं है तो कौन साथ खड़ा होगा? और प्राकृतिक तरीके से पैदा की गई फसल बाजार में पहुंचने के बाद क्या सामान्य फसल की तरह ही बिकेगी या किसान को कोई अतिरिक्त लाभ मिलेगा? ये छोटे सवाल नहीं हैं। इसीलिए प्राकृतिक खेती की बहस को सिर्फ ‘रसायनिक बनाम प्राकृतिक’ के खांचे में रखना ठीक नहीं होगा। हर इलाके की मिट्टी अलग है। पानी की उपलब्धता अलग है। फसलें अलग हैं। बाजार अलग है। किसान की आर्थिक स्थिति भी अलग है। जो तरीका एक इलाके में अच्छा काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वही दूसरे इलाके में भी उसी तरह परिणाम दे। सरकार के स्तर पर भी अब प्राकृतिक खेती को सिर्फ क्षेत्रफल बढ़ने के आंकड़े से देखने के बजाय उसके आर्थिक परिणामों पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 सितंबर की समीक्षा बैठक में किसानों की उत्पादकता, उत्पादन लागत, बाजार मूल्य और शुद्ध आय का तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिए। यानी यह देखने की जरूरत खुद सरकार मान रही है कि प्राकृतिक खेती से किसान को वास्तविक आर्थिक फायदा कितना हो रहा है।

यही बात सबसे महत्वपूर्ण है।

किसान के लिए खेत का आकार नहीं, खेत से बचने वाला पैसा मायने रखता है। कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती की चर्चा को किसान की लागत से जोड़ा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत पर बात की गई है। यह नजरिया बताता है कि खेती के तरीके में बदलाव केवल पर्यावरण का मामला नहीं है। उसके साथ किसान की आर्थिक सुरक्षा भी जुड़ी है।

अब जरा पानी की बात।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ‘पर ड्रॉप, मोर क्रॉप’ और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे दो करोड़ से अधिक किसानों को पानी बचाने में मदद मिल रही है। पानी बचाना आज सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। कई इलाकों में यह खेती बचाने का सवाल बन चुका है। यहीं क्लस्टरचरूजैसी योजना का महत्व सामने आता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2 अगस्त 2026 तक कृषि उपयोग के लिए करीब 11.49 लाख आकर-ग्रिड सोलर पंप लगाए जा चुके थे और 21.77 लाख से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए थे। योजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना और डीजल पर निर्भरता कम करना भी है। यहां पर्यावरण और किसान की जेब एक साथ दिखाई देती है। अगर सौर ऊर्जा से सिंचाई का खर्च घटता है तो

उसका फायदा किसान को है। लेकिन सोलर पंप लगाने की शुरूआती लागत, जमीन और पानी की उपलब्धता और योजना तक पहुंच भी उतने ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। किसी योजना का आंकड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन किसान तक उसकी पहुंच कैसी है, यह अलग सवाल है।

फसल विविधीकरण भी इसी कड़ी का हिस्सा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सरकार का फसल विविधीकरण कार्यक्रम धान जैसी अधिक पानी लेने वाली फसलों से कुछ क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और दूसरी फसलों की ओर ले जाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसका मकसद पानी की बचत के साथ मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना भी है।

लेकिन यहां फिर वही सवाल लौटता है। किसान धान छोड़कर दूसरी फसल क्यों लगाएगा? सिर्फ इसलिए कि वह पानी कम लेती है? किसान के लिए फसल का बाजार भी उतना ही जरूरी है। अगर वैकल्पिक फसल में पानी कम लगता है लेकिन खरीद की व्यवस्था कमजोर है, कामत अनिश्चित है या उपज बेचने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो किसान के लिए फैसला आसान नहीं होगा। ढूँढ़ने भी हाल के अध्ययन में अलग-अलग इलाकों में पानी की उपलब्धता, मिट्टी, जलवायु और बाजार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक फसल विविधीकरण पर जोर दिया है। यानी एक ही फार्मूला पूरे देश के लिए नहीं हो सकता।

यही बात जलवायु-अनुकूल फसलों पर लागू होती है। प्रधानमंत्री ने करीब तीन हजार जलवायु-अनुकूल किस्मों के विकास का उल्लेख किया है। बदलते मौसम में ऐसी किस्मों की जरूरत निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन नई किस्म विकसित हो जाना और किसान द्वारा उसे बढ़े पैमाने पर अपनाया जाना दो अलग बातें हैं। किसान को बीज, प्रशिक्षण, स्थानीय सलाह और बाजार—चारों चाहिए।

किसान की भाषा में सवाल बहुत सीधा है—मौसम खराब हुआ तो फसल बचेगी? और फसल बची तो दाम मिलेगा? जल संरक्षण की योजनाओं को भी इसी नजर से देखने की जरूरत है। अमृत सरोवर बने, वर्षाजल संचयन की संरचनाएं बनीं—यह अच्छी शुरुआत है। लेकिन उसके बाद का हिसाब भी होना चाहिए।

(लेखक - निमिषा सिंह)

पाकिस्तान में आतंक का पलटवार

कश्मीर के लिए पाली गई आतंकी फैक्टरी अब पाकिस्तान को ही निगल रही

पाकिस्तान के खेबर पख्तूनख्वा के कोहाट में सेना और आतंकियों के बीच करीब 20 घंटे चली मुठभेड़ में आठ आतंकी मारे गए। यह घटना पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही आतंकी हिंसा की उस तस्वीर का हिस्सा है, जिसमें आतंकवादी संगठन लगातार सुरक्षा बलों और नागरिकों के लिए चुनौती बने हुए हैं। कोहाट की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि आतंकवाद को लंबे समय तक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अब स्वयं उसी आतंक की आग में क्यों झुलस रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अगस्त 2026 तक पाकिस्तान में 990 आतंकी हमले हुए और इनमें 1126 लोगों की मौत हुई। आठ महीनों के आंकड़े यह बताते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए लगातार बड़ा खतरा बना हुआ है। अगस्त में 199 हमले दर्ज किए गए, जो इस वर्ष के शुरूआती आठ महीनों में किसी एक महीने में सबसे अधिक हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी में 87 आतंकी हमले हुए और 105 लोगों की मौत हुई। फरवरी में 83 हमलों में 139 लोगों की जान गई। मार्च में 106 हमलों में 146 मौतें दर्ज की गईं। अप्रैल में 85 हमले हुए और 60 लोगों की मौत हुई। मई में 160 हमलों में 128 लोगों की जान गई। जून में 112 हमले हुए और 118 मौतें दर्ज की गईं। जुलाई में 144 हमलों के साथ 268 मौतें हुईं, जबकि अगस्त में 199 हमलों में 158 लोगों की जान गईं।

कश्मीर के नाम पर तैयार आतंक का खेल अब पाकिस्तान पर भारी

पाकिस्तान ने लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर में भारत विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों को पनाह देने के आरोपों का सामना किया है। कश्मीर को भारत से अलग करने के उद्देश्य से आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करने की नीति ने लंबे समय तक क्षेत्र में हिंसा को जन्म दिया। आतंकवादियों ने नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और इसके कारण जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन आतंकवाद की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह जिस दिशा में भेजा जाता है, वहीं तक सीमित नहीं रहता। जिसका हिस्सा गतिविधियां यहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। खेबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आतंकवादी हिंसा के प्रमुख केंद्र हैं और इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को लगातार अभियान चलाने पड़ रहे हैं। कहते हैं कि बोए पैड़ बबूल के तो आम कहां से खाएं। कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने जिस आतंकवादी ढांचे को वर्षों तक सहारा दिया, उसका दुष्परिणाम आज पाकिस्तान के भीतर दिखाई दे रहा है। आतंकवादियों ने पाकिस्तान के नागरिकों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया है। जिस आतंकवाद को कभी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल करने का मासूम समझा गया, वही अब पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने वाला बड़ा कारण बन रहा है। आतंकवाद को किसी देश की नीति का औजार बनाना अतंतः उसी देश के लिए संकट पैदा कर सकता है। जब आतंकवादी संगठनों को संरक्षण, संसाधन या सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं तो उनके लिए लक्ष्य की सीमा तय रखना कठिन हो जाता है। एक संगठन दूसरे संगठन से जुड़ता है और अलग-अलग गुट अपने हितों के अनुसार हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान में उभरती आतंकी चुनौती इसी जटिल स्थिति को दर्शाती है।

आंकड़े बता रहे पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद

पाकिस्तान में 2026 के आंकड़ों का सबसे चिंताजनक पहलू हमलों की लगातार ऊंची संख्या है। आठ महीनों में 990 हमलों का अर्थ है कि औसतन हर महीने सौ से अधिक आतंकी घटनाएं दर्ज हुईं। अगस्त में 199 हमलों के साथ हिंसा का आंकड़ा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। जुलाई में 268 मौतों का आंकड़ा बताता है कि कम संख्या में हुए हमले भी कई बार अत्यधिक घातक साबित हुए। आतंकी हमलों में हुई मौतों और आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा अभियानों में हुई मौतों को अलग-अलग समझना जरूरी है। सुरक्षा अध्ययन संस्थाओं के आंकड़ों में कई बार आतंकवादी हमलों के साथ जनवरी कार्रवाई में मारे गए आतंकियों और सुरक्षा अभियानों में हुई अन्य मौतों को भी व्यापक संघर्ष आंकड़ों में शामिल किया जाता है। इसलिए अलग-अलग रिपोर्टों में कुल मौतों के आंकड़े अलग दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2026 में आतंकी हमलों में 105 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। वहीं आतंकवादी हिंसा और सुरक्षा अभियानों को मिलाकर व्यापक संघर्ष आंकड़ा 361 मौतों तक पहुंचा था। इसमें 242 आतंकी, 73 नागरिक और 46 सुरक्षा बलों के जवान शामिल बताए गए। जुलाई में 158 आतंकवादी हिंसा और सुरक्षा अभियानों को मिलाकर 606 मौतों का आंकड़ा सामने आया। इनमें 401 आतंकी, 112 सुरक्षा बलों के जवान, 74 नागरिक और 19 शांति समितियों से जुड़े लोग शामिल थे। वर्ष 2026 के शुरूआती चार महीनों में भी पाकिस्तान में 401 आतंकी हमले दर्ज किए गए थे। इस अवधि में 190 नागरिकों और 158 सुरक्षा बलों के जवानों की मौत का आंकड़ा सामने आया। सुरक्षा अभियानों में 988 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी भी दी गई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद केवल हमलों की संख्या का विषय नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ चल रहे सैन्य और सुरक्षा अभियानों ने भी देश के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद से दूसरे सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में रखा गया था। रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की हिंसक गतिविधियों में बड़ी वृद्धि का उल्लेख किया गया था। 2024 में इस संगठन से जुड़े 482 हमलों में 558 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया गया था।

(लेखक - कांतिलाल मांडोट)

भारत को डराया नहीं जा सकता, यह नया भारत है

हाल ही में अमेरिकी संसद द्वारा भारत एवं चीन सहित कुछ अन्य देशों से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने सम्बन्धी कानून को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, क्योंकि, ये देश रूस से कच्चे तेल का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। अमेरिका के अनुसार, इन देशों द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात के चलते रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध करने की आर्थिक शक्ति प्राप्त हो रही है। जबकि, यूरोपीयन देश एवं अमेरिका स्वयं रूस से गैस एवं अन्य उत्पादों का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। अर्थात, इन देशों द्वारा रूस से अन्य पदार्थों के आयात करने से रूस को कोई आर्थिक ताकत प्राप्त नहीं होती है, केवल भारत एवं चीन सहित कुछ अन्य देशों द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात से रूस को आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है। अमेरिका का यह दोहरा चरित्र अब पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित हो रहा है। अमेरिका को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर 100 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का उर दिखा कर एवं भारत को दबाव में लाकर अमेरिका भारत से अपने मनमाफिक निर्णय करवा लेगा, तो आज की बदली हुई परिस्थितियों के बीच यह सम्भव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका एवं पूरे विश्व के सामने अब एक नया भारत खड़ा है। अमेरिका दरअसल चाहता है कि भारत उसके कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोले ताकि वह भारत को अपने कृषि एवं डेयरी उत्पाद निर्यात कर सके। यदि भारत अमेरिका के इस दबाव में आता है तो भारतीय किसानों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और केंद्र सरकार भारत के किसानों के हितों की बलि किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। आज, संभवतः अमेरिका को भारत की अधिक आवश्यकता है क्योंकि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देशों की श्रेणी में उच्च स्थान रखता है। साथ ही, भारत आज विश्व में विभिन्न उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है एवं आगे आने वाले समय में भारत की यही स्थिति लम्बे समय तक बनी रहने वाली है। भारत आज विश्व के अन्य उत्पादक देशों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद आज विश्व में बड़े देशों के बीच सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जापान ने भारत की सार्वभौमिक क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। और तो और, अब अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी भारत की सार्वभौमिक क्रेडिट रेटिंग में सुधार करने पर विचार करने को मजबूर हो रही हैं। हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2026 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही, जेफरीज ने भी अपने पूर्व अनुमान 6.7 प्रतिशत को सुभाष्कर 7 प्रतिशत कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि भारत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में 7.8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की है।

भारत के अपने विदेशी उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने सम्बन्धित प्रयास आज सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि, अगस्त 2026 का माह भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत शानदार रहा है। वैश्विक स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियों के चलते भी भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में 26.12 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज हुई है। अगस्त 2025 माह में भारत के कुल निर्यात 3,474 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे थे जो अगस्त 2026 में बढ़कर 4,381 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हो गए हैं। फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आरगनाइजेशन के अनुसार, भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में हो रही आकर्षक वृद्धि दर भारतीय निर्यातकों की ताकत, प्रतिस्पर्धा व बाजार के हिसाब से ढलने की क्षमता को दर्शाती है। चीन, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, तंजानिया, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, स्पेन एवं श्रीलंका जैसे बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती पहुंच भारत के निर्यात बास्केट के विस्तार का संकेत है। आटोमोबाइल निर्यात में 22.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है, इसमें दोपहिया व तिपाहिया वाहनों का दबदबा रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में भी 3.14 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं इंजीनीयरिंग उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि भारत की मजबूत स्थिति को दर्शा रही है।

विदेशी व्यापार के मामले में भारत विश्व में केवल कुछ देशों (अमेरिका सहित) पर निर्भर रहने के स्थान पर अब अपने विभिन्न उत्पादों के निर्यात के लिए नए नए बाजार तलाश रहा है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों का सुपरिणाम दिखाई भी देने लगा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम पांच माह (अप्रैल-अगस्त 2026) के दौरान भारत का ब्रिक्स देशों (चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं रूस) को निर्यात 34 प्रतिशत बढ़कर 1,990 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है। इसी अवधि में चीन को भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। ब्रिक्स समूह के समस्त सदस्य देशों के साथ भारत अपने आर्थिक एवं राजनैतिक सम्बंध लगातार मजबूत कर रहा है, जिसका परिणाम अब इन देशों के साथ भारत के लगातार बढ़ रहे विदेशी व्यापार के रूप में दिखाई देने लगा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, ब्रिक्स के चार मुख्य देशों (चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं रूस) का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान 8.1 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान 9.2 प्रतिशत हो गया है। इस वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच माह के दौरान चीन को 960 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया है तो वहीं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं रूस को भारतीय उत्पादों के निर्यात में क्रमशः 58 प्रतिशत, 13 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज की गई है।

आज कई अमेरिकी कम्पनियां भारत में अपने वैश्विक योग्यता केंद्रों की स्थापना कर रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं - एस्ट्रा जेनेका, बैक ओफ अमेरिका, टरुब्रिज, गाइडवयर, आदि। भारत में स्थापित इन वैश्विक योग्यता केंद्रों में हजारों की संख्या में भारतीय इंजीनीयर कार्य कर रहे हैं। कहीं यह अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगातार बदले जा रहे वीजा सम्बंधी नियमों के चलते तो नहीं हो रहा है।

(लेखक - प्रहलाद सक्वानी)



नियम और कंपनी पर आधारित होता है नोटिस पीरियड

[illegible]

અવાધિ:

नोटिस पोरियड की अवधि आमतौर पर 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक हो सकती है। यह आपके पद, अनुभव और कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करता है। उदाहरण- जूनियर लेवल के लिए 30 दिन, सीनियर लेवल के लिए 60 दिन.

लिखित सूचना:

नौकरी छोड़ने की सूचना आमतौर पर लिखित रूप में (ईमेल या रिजाइनेशन लेटर) के जरिये देनी होती है। इसमें नोटिस पीरियड शुरू होने की तारीख और लास्ट वर्किंग डे की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इससे बाद में किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है।

काम करना:

नॉटिस पोरियड के दौरान सामान्य रूप से काम करना पड़ता है, जब तक कि कंपनी आपको पहले रिलीव न कर दे। वहीं कुछ मामलों में, कंपनी एक विकल्प दे सकती है, जहां आपको काम नहीं करना पड़ता पर आप तकनीकी रूप से अभी भी कर्मचारी रहते हैं।

सैलरी:

नोटिस पीरियड के दौरान भी पूरी सैलरी मिलती है। अगर आप नोटिस पीरियड पूरा नहीं करते हैं तो कंपनी आपसे उस अवधि की सैलरी वापस मांग सकती है। इसे आमतौर पर नोटिस पीरियड बाईआउट कहा जाता है।

कानूनी बाध्यता:

भारत जैसे देशों में, श्रम कानून नोटिस पीरियड को अनिवार्य करते हैं। अगर अनुबंध में लिखा है तो उसे मानना जरूरी होता है। यह बात कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों पर लागू होती है। इसमें सामान्य रूप से नोटिस पीरियड एक माह का होता है।

बारहवीं के बाद इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
और संस्थानों से करें एआई कोर्स



दाखिला ले सकते हैं। यह कोर्स आपको एआई की बारीकियों से अवगत करेगा। साथ ही चार साल के इस इस कोर्स को करके आप किसी संस्थान से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं।

आईआईटी मद्रास के कोर्स

आईआईटी मद्रास ने छात्रों के लिए स्वयं पोर्टल पर आईआईटी पर आधारित पांच ऑनलाइन कोर्स का शुुरुआत की है। इस कोर्स की खास बात ये है कि इन कोर्स में किसी भी स्ट्रीम के छात्र शामिल हो सकते हैं। साथ ही इन कोर्सेज की अवधि 25 से 45 दिन निर्धारित की गई है।

आईआईटी हैदराबाद

अगर आपको एआई में रुचि है, तो आप आईआईटी हैदराबाद से कक्षा बारहवीं के बाद बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में

कम्यूनिक्शन स्किल को भी बेहतर कर
सकेगें।

स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म

आगर आप बारहवीं पास छात्र हैं और एआई कोर्स का रख करना चाहते हैं, तो आप स्वयं पोर्टल के अलावा, स्थल इंडिया से भी एआई कोर्स कर सकते हैं। साथ ही कोसेरा, हार्वर्ड, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्स में भी शामिल हो सकते हैं। इन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एआई व एमएल कोर्स फ्री में उपलब्ध है। साथ ही इन कोर्स को पूरा करके आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं।

बीबीए या बीसीए के साथ इंटीग्रेटेड एलएलबी करें

आई दिल्ली, एजेंसी। 12वीं के बाद अगर आप वकालत लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बीबीए+एलएलबी या बीसीए+एलएलबी जैसे एडमिटेड कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए का फुल पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीए का बैचलर ऑफ कॉमर्शियल एप्लाइड साइंस है। अब इन दो कोर्सेस के साथ एलएलबी की पढ़ाई भी ले सकते हैं। समय के साथ ही करियर व्यवस्था भी बदलते जा रहे हैं। अब छात्रों के पास एक ही फील्ड में कई करियर विकल्प होते हैं। आजकल इटीग्रेटेड कोर्सेस का चलन बढ़ा है। इन कोर्सेस में दो अलग-अलग डिग्रियों की पढ़ाई एक साथ होती है। कौन खत्म होना के बाद स्टूडेंट को दोनों की मिलाकर एक डिग्री दी जाती है। अगर आप बीबीए या बीसीए के साथ लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कुछ बेस्ट ऑप्शन, बीबीए, बीसीए लॉ इटीग्रेटेड कोर्सेस (पांच साल) बीबीए+एलएलबी +एस इटीग्रेटेड कोर्सेस में बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ की पढ़ाई एक साथ होती है। इसमें जानिस से जुड़े विषयों (मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर) के साथ-साथ कानून के मूल सिद्धांत (कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ) पढ़ाए जाते हैं। बीबीए और बीसीए के बाद लॉ (3



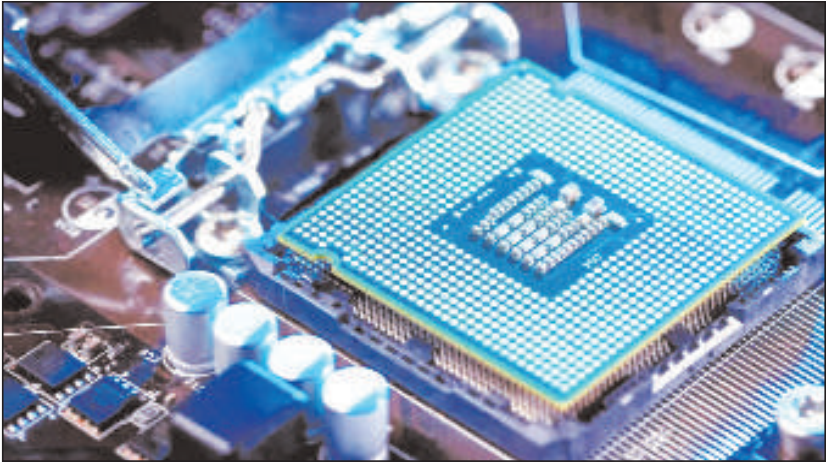
साल का एलएलबी) बीबीए या बीसीए कोर्स पूरा करने के बाद भी 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा

है, जो पहले बिजनेस या टेक्नोलॉजी में बेस बनाना चाहते हैं और फिर कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं। बीबीए के बाद-कांपॉरिट लॉ या बिजनेस लॉ में विशेषज्ञता ले सकते हैं। बीसीए के बाद-साइबर लॉ, डेटा प्राइवसी लॉ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में करियर बना सकते हैं। सैशलाइन्ड इंडिया या सर्टिफिकेट कोर्स बीबीए/बीसीए के साथ या बाद में आप लॉ से जुड़े शॉर्ट-टर्म कोर्स कर सकते हैं, जैसे- 1- साइबर लॉ (बीसीए के लिए) 2- कांपॉरिट लॉ (बीबीए के लिए) 3- इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आर्पीआर) यह कोर्स 6 महीने से 1 साल के हो सकते हैं और ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में उपलब्ध हैं। लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन इस प्रकार मिलेगा बीबीए एलएलबी के लिए एलजिबिलिटी- 12वीं पास (किंसी ही स्ट्रीम से), कम से कम 45-50 फीसदी अंको के साथ, कुछ कॉलेज में मैथ्स बोना अनिवार्य हो सकता है। प्रवेश परीक्षा कलेट नेशनल में यूनिवर्सिटीज के लिए, एआईएफएलजी एलएफ प्राइवेट लॉ कॉलेज के लिए, एमसी सीईटी महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए, प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा।

त्यापार

एआई निवेश से वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 2026 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर पार करेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में बढ़ते निवेश से वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार को तेज गति मिल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक यह बाजार 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक आंकड़े को पार कर जाएगा। यह अनुमान पहले लगाए गए अनुमानों से करीब डेढ़ गुना अधिक है। बाजार में इस तेजी को प्रमुख वजह अमेरिकी और चीनी हायरस्केक्टर कंपनियों का एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता निवेश बताया गया है। कोरिया एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक के रिसर्च सेंटर की ओर से वैश्विक बाजार अनुमान में कफिया के विश्लेषण के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे पहले लगाए गए अनुमान में 2030 तक बाजार के एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी। नए अनुमान से पता चलता है कि एआई से जुड़ी मांग में उद्योग के विकास की रफ्तार को काफी तेज किया है। रिपोर्ट के अनुसार बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर संचालित करने वाली अमेरिका और चीन की प्रमुख कंपनियों का एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर में लगातार



निवेश बढ़ा रही हैं। एआई सिस्टम में डेटा की मात्रा बढ़ने के साथ उच्च क्षमता वाली मेमोरी चिप्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा लाभ मेमोरी चिप निर्माताओं को मिल रहा है और वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का विस्तार हो रहा है। एआई उद्योग के कुछ

हिस्सों में तकनीक पर नियंत्रण खोने से जुड़ी चिंताओं के कारण इसके विकास की गति धीमी करने की मांग भी उठ रही है। इसके बावजूद सेमीकंडक्टर बाजार की रफ्तार फिलहाल बनी हुई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स

चीन पर निर्भरता घटाने के लिए 5,000 7,000 करोड़ की योजना की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। उद्योग निकाय एगो कम फंडेशन एअर आईडिया (एपीएफआई) ने कृषि रसायन तकनीकी और मध्यवर्ती उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार से 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये की सहायता योजना लाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे चीन के कम लागत वाले लाभ का मुकामला करने और भरेलु उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। एपीएफआई ने परामर्श फर्म केपीएमजी के सहयोग से तैयार रिपोर्ट में बात से आठ वर्ष की अवधि वाले कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पहले दो से तीन वर्षों में संयंत्र स्थापित करने और इसके बाद उत्पादन को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा सकती है। संगठन का मानना है कि इस तरह चरणबद्ध



तरीके से सहायता देने से उद्योग को उत्पादन क्षमता विकसित करने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का असर मिलेगा। रिपोर्ट में नई और मौजूदा विस्तार परियोजनाओं, दोनों को योजना में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत बड़ी और छोटी इकाइयों के लिए निवेश की क्रमिक सीमा तय करने का प्रस्ताव है। एसीएआई के अनुसार इस व्यवस्था से विभिन्न स्तर के उद्योगों को अपनी क्षमता बढ़ाने और

कृषि रसायन क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिल सकती है। एसोएफआर ने वृद्धिशील बिक्री पर पांच से आठ प्रतिशत प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा औद्योगिक बिजली और सड़क अपशिष्ट उपचार संयंत्रों पर 30 से 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। संगठन का कहना है कि उत्पादन लागत से जुड़ी इन चुनौतियों को दूर करना घरेलू कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है। रिपोर्ट में विशेष अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए पूंजीगत अनुदान देने की भी मांग की गई है। एसोएफआर के अनुसार कृषि रसायन तकनीकी और मध्यवर्ती उत्पादों के क्षेत्र में घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देना जरूरी है।

अमेरिकी टैरिफ से भारतीय कपड़ा उद्योग चिंतित, निर्यात पर बढ़ा संकट

नई दिल्ली, एंजेसी। अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़ा और परिधान नशियों पर शुल्कों का खतरा मँडराये से उद्योग की चिंता बढ गई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री (सीआईटीआई) ने कहा कि अमेरिका भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में वहाँ अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की स्थिति में भारतीय निर्यात पर सीधा असर पड सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लिंडसे ओ. ग्रहम सेंसशनल रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। इस फैसले ने भारतीय कपड़ा उद्योग की मुश्किलें बढा दी हैं। उद्योग को आशंका है कि यदि इस कानून के तहत भारत पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाया गया तो निर्यात कारोबार पर गंभीर दबाव पड सकता है। सीआईटीआई के वरिष्ठ अधिकारी चंद्रन ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की स्थिति में कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए इसका सामना करना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि खासतौर पर



छोटे और मझोले उद्योगों के सामने चुनौती अधिक गंभीर हो सकती है। ये उद्योग पहले से ही कई तरह की कारोबारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और परिचयम एशिया में जारी तनाव ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। चंद्रन के अनुसार नए शुल्क भारतीयों कर्पनियों के लिए अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद बेचना और कठिन बना सकते हैं। इससे भारत के कपड़ा और परिधान नरियत पर नकारात्मक दबाव पड़ने की आशंका है।



कपड़ा उद्योग के लिए इसलिए वहां कारोबार में भी बड़ी बाधा का असर बर्धियों पर पड़ सकता है। भारत से अमेरिका के साथ का आग्रह किया है, ताकि इस लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बाधाएं न आए। तब और अमेरिका के बीच निष्पक्ष, संतुलित और बराबरी वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। उद्योग का कहना है कि अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों से भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं, लेकिन उनका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। कंपनियों को नए बाजारों में अपनी स्थिति बनाने के लिए समय और लागतारा प्रयास की जरूरत होगी। इसलिए निकट भविष्य में अमेरिकी बाजार से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई इन नए बाजारों से करना आसान नहीं होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के अगले साल लागू होने की उम्मीद है। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। उद्योग को इन समझौतों से नए अवसर मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिनहलाल अमेरिकी शुल्क को लेकर चिंता बनी हुई है और सरकार से भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की अपील की गई है।

